

संपादकीय

रेलवे ने डी डी क्यू ई एल का सफल परीक्षण किया

भारतीय रेलवे नए तकनीकों को अपना कर विकाश के पथ पर निरंतर नया अध्ययन लिख रहा है। जो भारत के अलावे दुनिया के कई देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आजकल भारत में निमित्त रेल इंजन की कई देशों मांग हो रही है। वही रेलवे अपने पारम्परिक तकनीकी से सुधार व अनुसंसाधन कर कार्य प्रणाली को विकसित करने में लगातार प्रयासरत है। इसी श्रृंखला में विगत वर्ष एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेलवे ने डायरेट ड्राइव क्यूसन में इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग (ई एल) सिस्टम की अपनी ट्रैफिक व्यवस्था व सुरक्षा प्रणाली को लेकर परीक्षण के तौर स्थापित किया गया है। यह प्रणाली फिलहाल पश्चिम रेलवे रत्नाम मंडल के ताजपूर स्टेशन व उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल के दीनांगर देश की पहली सफल परीक्षण किया है। आपको बता दूँ कि यह नई व्यवस्था रेलवे के यातायात संचालन व सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता को विशेष रूप से ध्यान में रख कर बनाये गए हैं। इस संदर्भ में पश्चिम रेलवे के रत्नाम डिवीजन के आर एस मीणा, वरिष्ठ मंडल सिगनल एवं दूसरांचा अधिकार्यों के अनुसार पुराने पैनल इंटरलॉकिंग सिस्टम को हटाकर नए इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पहली बार पारंपरिक तकनीक के स्थान पर अन्यथानुक्रम डायरेट ड्राइव इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली को ताजपूर रेलवे स्टेशन पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इस नई प्रणाली के लागू होने से पश्चिम रेलवे, डायरेट ड्राइव सिस्टम को अपनाई गयी है। वहीं उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल द्वारा भी भारतीय रेलवे में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। इस नए प्रणाली के लागू होने से रेलवे के संचालन में दक्षता और सुरक्षा में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। इस नई प्रणाली की सफलता को लेकर जम्मू मंडल के रेल प्रबंधक विवेक कुमार ने डायरेट इंटरलॉकिंग सिस्टम की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में कहा कि यह प्रणाली रेलवे सिगनलिंग और पॉइंट मशीनरी को सीधे नियंत्रित करती है, जिससे मानवीय त्रुटि की संभावना कम हो जाती है। यह सिस्टन सुनिश्चित करता है कि ट्रेनों का सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित हो, जिससे दूर्घटनाओं का जोखिम कम हो। इस प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता ट्रेनों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करती है व ट्रेन संचालन की दक्षता में सुधार करती है। इस से यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव भी मिलेगा। भारतीय रेलवे इस प्रणाली को अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी लागू करने की योजना बना रही है। यह भारतीय रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित और कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ पर आप के मन में प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि यह डायरेट ड्राइव ई एल प्रणाली सिगनलिंग गियर को सीधे नियंत्रित करती है। जो एक कंयटर-आधारित प्रणाली है। जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई सिगनल केवल तभी किलयर हो जब ट्रेन संचालन की सभी सुरक्षा शर्तें पूरी हो चुकी हों, उदाहरण के लिए निम्न बिन्दु के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।

पहले की परंपरागत ई-एल सिस्टम में सिंगलिंग गियर को ऑपरेट करने के लिए अलग से रिले की आवश्यकता होती है, जबकि नए डायरेट ड्राइव ई एल प्रणाली में यह सीधे गियर को नियंत्रित करता है। यह प्रणाली गियर की स्थिति को स्वतः पहचानती है, जिससे मानवीय त्रुटियों की संभावना नगण्य हो जाती है। चूंकि रिले एक इलेक्ट्रो-पैकेजिनिकल डिवाइस है, इससे जुड़ी तकनीकी विफलताएँ भी डायरेट ड्राइव प्रणाली में बहुत कम हो जाती हैं। इस नए डायरेट ड्राइव ई एल से तकनीकी लाभ को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें ऑपरेटर फाइबर केबल के उपयोग से पारंपरिक कॉपर केबल की आवश्यकता तक कम हो जाती है, जिससे विद्युत प्रभाव से सुरक्षा मिलती है।

सबसे पहले रामेश्वरम की बात करें तो आपको बता दें कि यह स्थल रामायण और श्रीराम से जुड़ा है जोकि धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व रखता है। प्रधानमंत्री का वहाँ जाना दक्षिण भारत में हिंदू आस्था के प्रमुख केंद्रों को सशक्त करने का प्रयास माना गया। वहीं त्रिवी में चोल समाट राजेन्द्र प्रथम की जयती तस्वीर में प्रधानमंत्री की उपस्थिति तामिल गौरव और चोल इतिहास को ग्राहीय स्तर पर समानित करने का संदेश देती है। यह दिखाता है कि केंद्र सरकार तमिल संस्कृति और इतिहास को भारतीय सभ्यता के अधिन अंग के रूप में प्रस्तुत कर रही है।

प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्राएँ यह संरेश देती हैं कि तमिलनाडु का इतिहास और संस्कृति राष्ट्रीय गौरव का हिस्सा है, न कि उससे अलग। चोल समाट राजेन्द्र प्रथम जैसे ऐतिहासिक नायकों को ग्राहीय विमर्श में लाना, डीएमके के तमिल गौरव के नैटिव को चुनौती देने की

कोशिश भी है। इसके अलावा, त्रिवी यात्रा के साथ-साथ प्रधानमंत्री तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 24,800 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं। इससे यह संदेश जाता है कि सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक प्रगति एक-दूसरे के पूरक हैं। भारत इस संतुलन को दिखाकर तमिलनाडु की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि केंद्र सरकार क्षेत्रीय विकास और सांस्कृतिक सम्मान दोनों पर ध्यान दे रही है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गैंगोंडाचोलपुरम में समाट राजेन्द्र चोल प्रथम की जयती की योगीनी और आदित योगीनी और आदित योगीनी की उनकी उपस्थिति सीमित रही है। डीएमके के तमिल गौरव को चुनौती देने के लिए भारता ऐतिहासिक नायकों को हिंदूल के चर्चे से प्रस्तुत कर रही है। इससे उसे तमिलनाडु में सांस्कृतिक जुड़ाव बनाने का अवसर मिलता है। दोनों दलों की खांचतान के निहितार्थ पर गौरव करें तो डीएमके तमिल पहचान और द्राविड़ संस्कृति के प्रतिक हैं। पार्टी लंबे समय से यह तर्क देती रही है कि तमिल सभ्यता का इतिहास बेहद समझदार है और इसे उत्तर भारत केंद्रित ऐतिहासिक आख्यानों में दबा दिया गया। छूट्य चाहती है कि तमिल लोगों को यह एहसास हो कि उनके पूर्वजों ने समुद्र पार साप्राज्य खड़ा किया था। इसके अलावा, डीएमके इस विषय को ब्राह्मणवादी इतिहास लेखन के प्रतीक नहीं है, बल्कि गैंगोंडाचोलपुरम के भूजुंग और अधिकारी गैंगोंडाचोलपुरम के अपने-अपने वैचारिक ढांचे में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी देखने में आ रहा है कि भारता दक्षिण भारत में पैर जमाने के लिए क्षेत्रीय प्रतीकों को अपनाने की रणनीति पर काम कर रही है, जबकि डीएमके इस क्षेत्रीय अस्मिता को बचाने की कोशिश में हौली समाट राजेन्द्र प्रथम की विवासत पर कर रही यह खींचतान बताती है कि इतिहास के वल अतीत का विषय नहीं है, बल्कि वर्तमान की राजनीति का हथियार भी बनता है। डीएमके और भारता दोनों ही राजेन्द्र प्रथम को अपने-अपने वैचारिक ढांचे में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह संघर्ष आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति को और अधिक वैचारिक और सांस्कृतिक बहसों से भर देगा। बहाहाल, प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी का तूतीकोरिन से गैंगोंडाचोलपुरम तक का यह दौरा विकास और सांस्कृतिक प्रतीक वाला का एक संतुलित महोत्सव में शामिल होने के साथ ही राजेन्द्र चोल प्रथम पर एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे। यह समारोह चोल साप्राज्य की समुद्री विजय के 1000 वर्ष पूरे होने और गैंगोंडाचोलपुरम मंदिर के निर्माण की स्मृति में आयोजित हो रहा है।

चोल समाट राजेन्द्र प्रथम को लेकर भाजपा और द्रमुक में क्यों हो रही है खींचतान?

नीरज कुमार दुबे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राओं में एक स्पष्ट रणनीतिक और सांस्कृतिक संदेश छिपा हुआ होता है। ऐसा ही संदेश प्रधानमंत्री की तमिलनाडु यात्रा में भी छिपा है। हम आपको याद दिला दें कि इस साल अप्रैल में श्रीलंका से लौटते समय प्रधानमंत्री सीधे रामेश्वरम पहुँचे थे और अब मालदीव से लौटते समय सीधे तमिलनाडु के तूतीकोरिन और त्रिवी आ रहे हैं, जहाँ वह चोल समाट राजेन्द्र प्रथम की जयंती उत्सव और आदि तिरुवायिरे महोत्सव में भाग लेंगे। यह यात्रा केवल धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उपस्थिति भर नहीं है, बल्कि तमिलनाडु और द्रमुक भारत की राजनीति में एक बड़ा संकेत है।



सबसे पहले रामेश्वरम की बात करें तो आपको बता दें कि यह स्थल रामायण और श्रीराम से जुड़ा है जोकि धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व रखता है। प्रधानमंत्री का वहाँ जाना दक्षिण भारत में हिंदू आस्था के प्रमुख केंद्रों को सशक्त करने का प्रयास माना गया। वहीं त्रिवी में चोल समाट राजेन्द्र प्रथम की जयंती तस्वीर में प्रधानमंत्री की उपस्थिति तामिल गौरव और चोल इतिहास को ग्राहीय स्तर पर समानित करने का संदेश देती है। यह दिखाता है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि केंद्र सरकार क्षेत्रीय विकास और सांस्कृतिक सम्मान दोनों पर ध्यान दे रही है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गैंगोंडाचोलपुरम में समाट राजेन्द्र चोल प्रथम की जयंती की योगीनी और आदित योगीनी की उनकी उपस्थिति सीमित रही है। डीएमके के तमिल गौरव को चुनौती देने के लिए भारता ऐतिहासिक नायकों को हिंदूल के चर्चे से प्रस्तुत कर रही है। इससे उसे तमिलनाडु में सांस्कृतिक जुड़ाव बनाने का अवसर मिलता है। दोनों दलों की खांचतान के निहितार्थ पर गौरव करें तो डीएमके तमिल गौरव के चुनौती देने के लिए भारता ऐतिहासिक नायकों को अपनाने की रणनीति पर काम कर रही है, जबकि डीएमके इस क्षेत्रीय प्रतीकों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह संघर्ष आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति को और अधिक वैचारिक और सांस्कृतिक

